



उत्तराखण्ड सरकार
प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून

E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 05 नवम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-05(11/20)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को डोईवाला स्थित माजरी ग्रांट में मिलिट्री ईक्यूपमेंट परिवार की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लघु ईकाई के रूप में विकसित मिलिट्री ईक्यूपमेंट परिवार अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने इस लघु इकाई के संस्थापक विनोद कुमार के सराहनीय प्रयासों पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर अधिकतम लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि छोटे तबके के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक कल्चर विकसित होना जरूरी है।

इस अवसर पर श्री ओ.पी. सबरवाल, बी.पी.एस खात, श्री ए.एस. बिष्ट, श्री वार्ड.बी थापा आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा सोमवार को आंगनबाड़ी केन्द्र, बड़कुली मालसी में राष्ट्रीय पोषण मिशन "पोषण अभियान" के अन्तर्गत कुपोषण को दूर करने एवं जनसामान्य में कुपोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित कार्यक्रम "अंधेरे से उजाले की ओर" का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा लाभार्थियों को टेक होम राशन के अन्तर्गत पोषाहार का वितरण भी किया गया।

श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुपोषण के अंधेरे को सुपोषण के उजाले से दूर करना तथा जन सामान्य को कुपोषण के दूरगामी दुष्प्रभावों के विषय में जागरूक कर राज्य में कुपोषण को कम करना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन "पोषण अभियान" के अन्तर्गत कुपोषण को दूर करने एवं जनसामान्य में कुपोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा राज्य में दीपावली के शुभ अवसर पर कुपोषण के अंधेरे को दूर करने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दीप जलाकर कुपोषण को खत्म करने हेतु कार्यक्रम रखा गया है।

कार्यक्रम में बड़कुली केन्द्र की गर्भवती व धात्री मातायें तथा लाभार्थी बच्चों के द्वारा भी दीपदान कार्यक्रम में भाग लिया गया था कुपोषण को दूर करने की शपथ ली गई।

इस अवसर पर उपनिदेशक/नोडल अधिकारी (एन.एन.एम) श्रीमती सुजाता, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून श्रीमती क्षमा बहुगुणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती आशा रानी ध्यानी एवं ग्राम प्रधान मालसी श्रीमती संगीता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व आंगनबाड़ी सहायिका उपस्थित रहीं।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि नागरिक विशेषकर युवा वर्ग विकास व सामाजिक कार्यों हेतु सरकारों पर निर्भरता को कम करने का प्रयास करे, स्वप्रेरणा से सामाजिक दायित्व निभाए। मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं का आह्वाहन किया कि ऐसे प्रयास किए जाए कि युवाओं की क्षमता, योग्यता, ज्ञान, स्किल, धन, विशेषज्ञता का उपयोग व्यापक सामाजिक विकास व कल्याण के लिए हो। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट व प्रोफेशनल अन्तिम व्यक्ति व अन्तिम गांव के विकास में अपनी भूमिका तय करे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री सेवा योजना के तहत "मेरा सामाजिक दायित्व-स्वर्णिम उत्तराखण्ड" में बतौर प्रतिनिधि प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देश की आजादी के 71 वर्षों के बाद भी हम सरकारों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। यह निर्भरता सोने-चांदी की बैसाखी जैसी है। हमें गम्भीरता से विचार करना होगा कि हम स्वयं समाज, राज्य व देश के लिए क्या कर सकते हैं। हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। हमारी स्किलस व विशेषज्ञता दूरस्थ गांवों के विकास में काम आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों की अपेक्षा हमारे गांवों में सामाजिक उत्तरदायित्व बखूबी निभाया जाता है। ग्रामीण समाज परस्पर सहायता, सहयोग व सौहार्द में विश्वास करता है। उन्होंने छात्र-छात्राओं का आह्वाहन किया कि समाचार पत्रों का नियमित अध्ययन अवश्य करें। समाचार पत्रों के नियमित अध्ययन से समाज की समस्याओं की जानकारी के साथ ही समाज के प्रति संवेदनाएं जागृत होती हैं तथा समाज के प्रति जुड़ाव बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों को सामाजिक उत्तरदायित्व का आभास होगा। उन्होंने कहा कि हमारी साक्षरता दर अच्छी है। प्रत्येक वर्ष लगभग ढाई से तीन लाख छात्र-छात्राएं बारहवी की परीक्षा पास करते हैं। यदि सभी छात्र-छात्राएं एक-एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले तो राज्य में सौ प्रतिशत साक्षरता शीघ्र ही प्राप्त की जा सकती है। आज दुनियाभर में सामाजिक कार्यों का महत्व बढ़ गया है। इसके साथ ही बच्चों में उद्यमशीलता व प्रोफेशनलिज्म का विकास करना होगा। युवाओं को मात्र नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए व उद्यमशीलता की ओर बढ़ना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा हमारे युवा टेक्नोक्रेट व प्रोफेशनल राज्य की 670 न्याय पंचायतों को आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नए टेक्नाक्रेट व प्रोफेशनल को हमारे गांव की परम्परागत आर्थिकी, दैनिक उत्पादन कार्यों व ग्रामीण जीवन का अध्ययन करना चाहिए तथा आधुनिक तकनीक व स्किलस द्वारा ग्रामीणों के जीवन के सुधार के उपायों पर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के 95 विकासखण्डों का 95 इन्सटिट्यूट व 95 औद्योगिक आस्थानों द्वारा विकास किए जाने की योजना पर ठोस कार्ययोजना से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे 25 विकासखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर है। हमे सीमान्त क्षेत्रों के विकास व कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना होगा। सीमान्त गांव सामरिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील व महत्वपूर्ण है। सेना को भी सीमान्त ग्रामीणों से सामरिक व देश की सुरक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार श्री नरेन्द्र सिंह, उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास व पलायन आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस.एस. नेगी, उत्तरांचल टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री वी. के. सिंह आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और जल मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी व उत्तराखण्ड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में भारत सरकार की कंपनी वेपकोस (Wapcos) और आस्ट्रिया की कंपनी डोपलमेयर (Doppelmayr) के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

एमओयू के तहत देश के विभिन्न राज्यों में यात्री सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रोपवे प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। साथ ही वेपकोस व डोपलमेयर संयुक्त रूप से केबिल कार की सम्भाव्यता का भी अध्ययन करेंगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

बी.आर.ओ. (सीमा सड़क संगठन) द्वारा राज्य की सड़को के निर्माण में नवीन तकनीकी इस्तेमाल के द्वारा पर्यावरणीय हानि को कम से कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। सड़को के निर्माण में अवशेष सामग्री (सड़को के कटान के दौरान होने वाला मलबा आदि) को

प्राथमिकता के साथ पुनःप्रयोग किया जा रहा है। बी.आर.ओ. द्वारा सड़को के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में 18 हजार करोड़ की लागत से चीन की सीमाओं तक कनेक्टिविटी हेतु मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बैजनाथ-थराली-कर्णप्रयाग मार्ग, अस्कोट-धारचूला-मालपा-लिपुलेख मार्ग, बैजनाथ -बागेश्वर -कपकोट -मुनस्यारी -सेराघाट-जौलजीवी मार्ग, माना-मूसा पानी-माणा पास तथा जोशीमठ-मलारी मार्ग सम्मिलित है। सीमा सड़क संगठन ने राज्य में सड़कों के निर्माण हेतु फॉरेस्ट किलयरेन्स, भूमि-अधिग्रहण, व सम्बन्धित विषयो हेतु शीघ्रता से अनुमोदन व सकारात्मक सहयोग हेतु सरकार व प्रशासन का आभार प्रकट किया। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ले.जनरल हरपाल सिंह ने राज्य के सीमान्त सड़को के निर्माण से जुड़े विभिन्न बिन्दुओ पर विस्तृत चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हरिद्वार रोड़ पर सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट मुख्यालय हेतु अतिरिक्त 20 एकड़ भूमि की अनुरोध पर गम्भीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बी.आर.ओ. के भूमि अधिग्रहण, फॉरेस्ट किलयरेन्स व अन्य मामलों के शीघ्र से शीघ्र निपटान हेतु निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा राज्य के सीमान्त क्षेत्रों व गांवों में रोड़ कनेक्टिविटी सामरिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील व महत्वपूर्ण है। सेना को भी सीमान्त ग्रामीणों से सामरिक व देश की सुरक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन के साथ हर संभव सहयोग की बात कही।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश व बी.आर.ओ. के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग